



झुंझुनू जिले में बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं

डॉ. बंशीधर

सहाय्यक आचार्य - भूगोल विभाग

श्री श्रद्धानाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोडी (गुढा गौडजी) झुंझुनू, राजस्थान.

सारांश:

झुंझुनू जिले में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। झुंझुनू जिले में उचित पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन की नीतियों का अभाव है। जिले की समस्त तहसीलों में पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ा है। चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण वायु प्रदूषण जिले में यह सभी प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण में मुख्य रूप से वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण आदि को प्रदूषण शहर को प्रभावित कर रहे हैं। उचित पर्यावरण प्रबंधन एवं के अभाव में जिले में यह समस्या तेज गति से बढ़ रही है।

प्रस्तावना:

असंतुलित होते पर्यावरण के कारण आज मनुष्य के जीवन पर आपदाएं आ रही हैं बल्कि कई पशु पक्षियों की प्रजातियां सदैव के लिए लुप्तप्राय सी होती जा रही हैं। वस्तुतः झुंझुनू जिले में कारक पाया गए हैं। जिनके द्वारा उच्च स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जिले में पर्यावरण प्रदूषण निरंतर गति से बढ़ रहा है एवं उचित नीतियों का अभाव तथा वर्तमान नीतियों के सही क्रियान्वयन के अभाव के कारण जिले में या समस्या निरंतर विकराल होती जा रही है।

अध्ययन के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि झुंझुनू जिले में उचित पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन की सुदृढ़ नीतियों का अभाव पाया जाता है जिस कारण जिले में विभिन्न रूपों में पर्यावरण प्रदूषण अपने पांव पसार रहा है। झुंझुनू जिले में विभिन्न प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं जिले में उत्पन्न हो गयी हैं वस्तुतः बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण से जिले में निम्न समस्याएं बढ़ी हैं।

CORRESPONDING AUTHOR:	RESEARCH ARTICLE
<p>Dr. Banshidhar Assistant Professor Shree Shradhdhanath PG College, Todi (Gudhagorji), Jhunjhunu. Rajasthan. Email: dr.jhajhria1978@gmail.com</p>	

झुंझुनी: झोपड़ियों का विकास-

झुंझुनू जिले में निरंतर बढ़ते नगरीकरण के कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में झुंझुनी झोपड़ियों का विकास हुआ है। ज्यादातर इन क्षेत्रों में गैरकानूनी रूप से बसे हुए लोग रहते हैं जो कई सारी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

पानी की कमी -

झुंझुनू जिले में भूजल ही जल प्राप्ति का एकमात्र साधन है, जनसमुदाय द्वारा पीने एवं कृषि कार्यों दोनों में ही जल की आपूर्ति भूजल के माध्यम से जाती है। जिले में जल के अनुचित दोहन के कारण भूजल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है एवं पर्याप्त वर्षा ना होने के कारण इस जल का पुनर्भरण भी नहीं हो पाता है तो स्थिति और विकट बनती जा रही है।

साफ: सफाई की समस्या-

जिले में नगरीय क्षेत्रों में जनसँख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है जिस कारण से सघन आबादी वाले क्षेत्रों में साफ सफाई की समस्या भी देखने को मिली है जिस कारण से जिले में विभिन्न प्रकार की बीमारिया भी फैल रही है।

खराब स्वास्थ्य :

निरंतर बढ़ते विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण झुंझुनू जिले में जनसमुदाय विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं जिले में बढ़ते , इनसे संबंधित व वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण ,जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार संक्रामक रोग जिले फैल रहे हैं।

कचरा निस्तारण की समस्या:

झुंझुनू जिले में निरंतर बढ़ती जनसँख्या एवं बढ़ते नगरीकरण के कारण जिले में कूड़े कचरे के निस्तारण की समस्या भी उत्पन्न हो गयी है। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी खाली पड़ी भूमि में कचरे का निस्तारण नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है परन्तु शहरी क्षेत्र में निष्काषित घरेलू अपशिष्ट एवं कचरे के निस्तारण की समस्या जिले में बनी रहती है।

जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की समस्या :

प्रस्तुत अध्ययन के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि झुंझुनू जिले में बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण कारण जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की समस्या को भी न्योता दिया है। जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की समस्या का सीधा स भूमि की गुणवत्ता से भी है।

पोषनीयता की समस्या :

जैसा की अध्ययन के पंचम अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है कि झुंझुनू जिले में कृषि आधुनिकीकरण के कारण कृषि का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। वर्तमान समय में जिले में कृषक अधिक उपज की लालसा एवं कम समय में अधिक उत्पादन

प्राप्त करने के लालच में विभिन्न प्रकार के खतरनाक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं जिस कारण जिले में भूमि की उर्वरा शक्ति का हास हो रहा है एवं पोषणीयता की समस्या निरन्तर बढ़ रही है।

जिले में पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण एवं पर्यावरण प्रबंधन हेतु सुझाव :

प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात होता है की जिले में पर्यावरण प्रदूषण निरंतर गति से बढ़ रहा है एवं उचित नीतियों के अभाव तथा वर्तमान नीतियों के सही क्रियान्वयन के अभाव के कारण जिले में यह समस्या निरंतर विकराल होती जा रही है। जिले में पर्यावरण के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित सुझावों को अपनाकर कुछ हद तक समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

जल प्रबंधन हेतु सुझाव :

विश्व में भूजल प्रबन्धन इस तरह किया जाता है कि उपलब्ध समस्त भूजल का प्रतिशत से अधिक उपयोग में नहीं 70 किये जा लिया जाये ताकि भविष्य हेतु जल संरक्षित किया जा सके। यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक संसाधन पैदा नहीं सकते लेकिन समुदाय के प्रयासों से भूजल संरक्षित एवं पुनर्भरित किया जा सकता है। इसलिये जल प्रबन्धन का केन्द्र बिन्दु जल संरक्षण करें तो ही जल संकट से निपटा जा सकता है।

घरेलू अथवा व्यक्तिगत स्तर पर :

घरेलू निष्कासित जल का बगीचों आदि में पुनः उपयोग करना एवं घरेलू अनलों से व्यर्थ पानी न बहाना। खाना पकाने के लिये छोटे आकार के बर्तन व समुचित मात्रा में पानी का उपयोग घरों में वर्षाजल संग्रहण हेतु व्यवस्था करना ताकि घरेलू , घरों व होटलों में कार्य हेतु भूजल दोहन के दबाव को कम किया जा सके। सार्वजनिक नल आदि से जल को न बहने दें। फव्वारों से नहा कर जल बर्बाद न करें। शौचालय में कम क्षमता के सिस्टम लगाना। प्रत्येक घर में वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण हेतु पुनर्भरण संरचना बनाई जाए जिससे भूजल भंडारों में बढ़ोत्तरी की जा सके।

कृषि क्षेत्र स्तर पर

फव्वारा व बूँदप्रतिशत तक ब 60 से 40 ई पद्धति को अपनाना ताकि पानी की बूँद सिंचा-चत की जा सके कम पानी के उपयोग वाली फसलों को उगाकर लगभग उपयुक्त | प्रतिशत तक पानी बचाया जा सकता है। उचित मात्रा में 40 से 30 खाद व कीटनाशक दवाईयों का उपयोग करना ताकि शुद्ध जल को प्रदूषण से बचाया जा सके।

घरेलू अथवा व्यक्तिगत स्तर पर:

घरेलू निष्कासित जल का बगीचों आदि में पुनः उपयोग करना एवं घरेलू नलों से व्यर्थ पानी न बहाना। खाना पकाने के लिये छोटे आकार के बर्तन व समुचित मात्रा में पानी का उपयोग घरों में वर्षाजल संग्रहण हेतु व्यवस्था करना ताकि घरेलू , कार्य हेतु भूजल दोहन के दबाव को कम किया जा सके। सार्वजनिकनल आदि से जल को न बहने दें घरों व होटलों में

फव्वारों से नहा कर जल बर्बाद न करें। शौचालय में कम क्षमता के सिस्टम लगाना। प्रत्येक घर में वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण हेतु पुनर्भरण संरचना बनाई जाए जिससे भूजल भंडारों में बढ़ोत्तरी की जा सके।

कृषि क्षेत्र स्तर पर

फव्वारा व बूंदप्रतिशत तक बचत की जा सके। कम पानी के 60 से 40 बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाना ताकि पानी की-कत खाद प्रतिशत तक पानी बचाया जा सकता है। उचित मात्रा में उपयुक्त 40 से 30 उपयोग वाली फसलों को उगाकर लगभग व कीटनाशक दवाईयों का उपयोग करना ताकि शुद्ध जल को प्रदूषण से बचाया जा सके।

औद्योगिक स्तर पर

सभी उद्योगों को उपयोग में लाये गये पानी की प्रतिशत मात्रा को पुनः उपयोग हेतु रिसायकलिंग आवश्यक करना सभी 80 चाहिये। उद्योगों में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण अनिवार्य होना

सामुदायिक स्तर पर

नलकूप एवं हैण्डपम्प आदि के आस-पास भरे हुये जल को पुनर्भरण संरचनाएँ बनाकर कृत्रिम रूप से भूजल का पुनर्भरण करें एवं इस भरे एकत्रित जल को व्यर्थ नहीं जाने दें वर्षा से होने वाले वार्षिक भूजल पुनर्भरण की गणना कर स्वयं फैसला करें कि कितना भूजल निकाला जाना है अनुपयोगी कुँओं,

- भूमि के क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण, बांध-बंधियां आदि बनाये जाने चाहिए। नवीन कीटनाशकों का विकास किया जाये जो अन्य लक्ष्यगत कीटों के अतिरिक्त अन्य जीवाणुओं को नष्ट कर सके। कृषि कार्यो में जैविक खाद व दुर्बल कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- पौधारोपण एवं अधिक से अधिक हरी घास को लगाकर भूमि कटाव को रोका जाना।
- औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित कचरे को ठिकाने लगाने के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। कचरा निस्तारण के लिए नगर पालिकाओं के सख्त नियम बनाये जाने चाहिए।
- कृषि अवशेषों को खेतों में न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

झुंझुनू जिले में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से अनेक समस्याएं बढ़ी है। जिले में निरंतर बढ़ते नगरीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की समस्याओं की जड़ पर्यावरण प्रदूषण ही है। झुंझुनू जिले में बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की समस्या को भी न्योता दिया है। जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की समस्याओं का सीधा संबंध भूमि की गुणवत्ता से भी है।

सुंदरुडु :

1. Arndt, H. W., (1981) - "Economic development: a semantic history," Economic Development and Cultural Change, Vol. 29, No. 3, pp. 457-466
2. Barbier, E. B., (1987) - "The concept of sustainable economic development. "Environmental Conservation, Vol. 14, No. 2 (1987), pp. 101-110.
3. Bartelmus, P. (1986)Environment and Development (London: Allen & Unwin.).
4. Blaikie, P., (1985)Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries (London: Longman).
5. Brandt Commission, North-South (1980): A Programme for Survival (London: Pan Books).
6. Brown, L. R., (1981)Building a Sustainable Society (New York: W. W. Norton).
7. Chambers, R. (1988) Sustainable Livelihoods: An opportunity for the World Commission on Environmental and Development (Brighton. UK: Institute of Development Studies, University of Sussex).
8. Charoenwatana, T., and A. T. Rambo, (1988) "Preface," in T. Charoenwatana and A. T+ Rambo (Eds.), Sustainable Rural Development in Asia (Khon Kaen, Thailand: KKU-USAID Farming Systems Research Project. Khon Kaen University and Southeast Asian Universities Agroecosystem Network). pp. viiX.
9. Chong, H.G., (2008), "The Environmental Management System as a Competitive Advantage Tool for Organizations", The Journal of Accounting and Finance, The Research Development Association, Jaipur, OctoberMarch, Vol.22, No. 1, pp. 71-78.10.
10. Clark, W. C., and R. E. Munn (Eds.), (1986) - Sustainable Development of the Biosphere (Cambridge: Cambridge University Press).
11. Committee on Agricultural Sustainability in Developing Countries (1987) -The Transition to Sustainable Agriculture: An agenda for AID (Washington, DC: International Institute for Environment and Development).

